(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया): (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। संसद की स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि नया पासपोर्ट कार्यालय उन्हीं क्षेत्रों/नगरों में स्थित होना चाहिए जहां एक वर्ष में 50,000 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हों। नए पासपोर्ट कार्यालयों का खोला जाना कुछ मानदण्डों पर आधारित है जैसे कि कार्य की मात्रा और सरकार के पास उपलब्ध संसाधन। हमारा अनुभव यह है कि नए पासपोर्ट कार्यालय खोल देने मात्र से सेवाओं में सुधार नहीं होता जब तक आवश्यक आधारभूत सुविधाएं तथा कार्मिक उपलब्ध न हों।

गुजरात के जामनगर जिले में मोटी खावडी स्थान में गैस-आधारित परियोजनाओं को गैस का आवंटन

349. **श्री कनक सिंह मोहन-सिंह मंगरोला:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के जामनगर जिले में मोटी खावडी स्थान पर निजी पार्टियों/कम्पनियों द्वारा स्थापित की जाने वाली गैस आधारित परियोजनाओं को कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस का आवंटन किया गया;

(ख) क्या सरकार ने गैस के आवंटन के लिये कुछ मानदंड अपनाये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) गुजरात में जामनगर जिले के मोटी खावडी में किसी भी परियोजना के संबंध में गैस का कोई आवंटन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) गैस के उपयोग को इष्टतम करने के लिए गैस का आवंटन विद्युत और उर्वरक क्षेत्रों के संबंध में वरीयता के अधीन सामान्यतया गैस उपयोग के आरोपित आर्थिक मूल्य पर आधारित होता है।

(घ) और (ङ) राज्य में विद्युत और अन्य परियोजनाओं के लिए गैस के आवंटन के संबंध में गुजरात सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। गुजरात में परियोजनाओं को 23.24 एमएमएससीएम प्रतिदिन आवंटित किया गया है। चूंकि उपलब्ध होने वाली अनुमानित गैस पूरी तरह से आवंटित है, इसलिए वर्तमान समय में और अधिक आवंटन करना व्यवहार्य नहीं है।

Telephone Connections Sanctioned to Surat City

350. SHRI KANAKSINGH MOHANSINGH MANGROLA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) what is the number of telephone connections sanctioned for Surat Telephones for the Calendar years 1991, 1992, 1993, 1994 and up to 30th June, 1995;

(b) whether any criteria for the need of telephone connections for Surat city were fixed while sanctioning those connections; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATION (SHRI SUKH RAM): (a) to (c) The required information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Purchase of Mirage Aircraft by Pakistan from France

351. SHRI T. VENKATRAM REDDY:
SHRI G. PRATHAPA REDDY:
SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Pakistan intends to purchase Mirage combat aircrafts from France;

(b) whether the Union Government

have conveyed their concern to France in this regard; and

(c) if so, the details thereof and the reaction of France thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) Government have noted reports about the proposed purchase by Pakistan of 40 Mirage fighter aircraft from France.

(b) and (c) Yes, Sir. We have taken up the matter with the government of France, and made clear our concern, drawing their attention to the adverse impact the sale of these aircraft would have on our security, as well as on stability in the region. They have stated that this subject has been discussed between the manufacturer and Pakistan, but that they have not taken a decision regarding the sale.

Degradation of Chandaka-Dampara Wild-life Sanctuary in Orissa

352. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the growing degradation of Chandaka-Dampara wild life sanctuary in Orissa;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the steps taken to save that wild-life sanctuary from extinction; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI RAJESH PILOT): (a) no reports have been received about degradation in the Chandaka-Dampara Sanctuary of Orissa.

(b) Does not arise.

(c) and (d) The steps taken to protect the sanctuary and its wild life include :

(i) The vulnerable parts of the sanctuary boundary have been protected by solar electric fencing and trench to prevent movement of elephants into inhabited areas.

(ii) Habitat development has been undertaken through regeneration of indigenous tree species, planting of fruit bearing species, creation of meadows etc.

(iii) Development of road and wireless network to facilitate better communication has been undertaken.

(iv) Relocation of some villages from inside the sanctuary has also been undertaken.

(v) Central assistance is provided by this Ministry for the development of the sanctuary under schemes of National Parks & Sanctuary, eco-development, and Project Elephant.

हज यात्रियों पर होने वाला खर्च

353. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष कितने भारतीय मुसलमान हज यात्रा पर गये;

(ख) प्रत्येक हज यात्री को विमान यात्रा के लिये सरकार ने कितनी राज-सहायता दी;

(ग) राज-सहायता पर सरकार ने कुल कितनी राशि खर्च की; और

(घ) हज यात्रा के लिये सरकारी प्रतिनिधि मंडल पर कुल कितनी राशि खर्च हुई?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया): (क) हज 1995 के लिए, केन्द्रीय हज समिति द्वारा किए गए इन्तजा-मातों के तहत 31,000 भारतीय हाजी हज करने के लिए सऊदी अरब की यात्रा पर गए।

(ख) हज 1995 के लिए हज चार्टर किराए और हज यात्रियों को दिए गए रियायती वायुयान किराए के बीच 5500 रुपए प्रति हाजी अन्तर था।

(ग) सरकार द्वारा रियायती वायुयान किरायों के संबंध में हज 1995 के लिए कुल 17.05 करोड़ रुपए की राशि का भार वहन किया गया था।

(घ) रियायती वायुयान किराए पर व्यय के अलावा